



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 504] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1974/अग्रहायण 21, 1896

No. 504] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 1974/AGRAHAYANA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 12th December 1974

S.O. 710(E)/18FB/IDRA/74.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 200(E)/18FB/IDRA/73, dated the 5th April, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the Industrial undertaking known as the Refractory Plant near Ramgarh in Hazaribagh District in the State of Bihar belonging to Messrs Assam Sillimanite Limited is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended up to the 30th June, 1973 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 30th June, 1973;

And whereas the Central Government in the Ministry of Industrial Development by orders No. S.O. 362(E)/IDRA/73, dated the 30th June, 1973, No. S.O. 452(E)/18FB/IDRA/73, dated the 30th August, 1973, No. S.O. 796(E)/18FB/IDRA/73, dated the 28th December, 1973 and No. S.O. 402(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th June, 1974, extended the duration of the said Order upto the 31st August, 1973, 31st December, 1973, 30th June, 1974 and 31st December, 1974, respectively.

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended further upto the 30th June, 1975;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 30th June, 1975.

[No. F.25/8/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पुंति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1974

का० आ० 710(अ)/18 चख/आई०डी०आर०ए०/74.—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय में आदेश सं० का० आ० 200 (ई) 18चख/आई०डी०आर०ए०/73, तारीख 5 अप्रैल, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया था कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों व्यवस्थापनों, पंचाटों या अन्य लिखतों का या उनमें से किसी का, जिलका मेसर्स आसाम सिलीमेनाइट लिमिटेड का बिहार राज्य के हजारी बाग जिला में रामगढ़ के निकट रिफ़ैक्टरी प्लाण्ट नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों या हो, प्रवर्तन 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व नद्वीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेंगे।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश, सं० का० आ० 362(ई)/आई०डी०आर०ए०/73, तारीख 30 जून, 1973, सं० का० आ० 452 (ई)/18 चख/आई०डी०आर०ए०/73, तारीख 30 अगस्त, 1973 सं० का० आ० 796 (ई)/18 चख/आई०डी०आर०ए०/73 तारीख 28 दिसम्बर, 1973 और सं० का० आ० 402 (ई)/18 चख/आई०डी०आर०ए०/74, तारीख 29 जून, 1974 द्वारा उक्त आदेश की अवधि क्रमशः 31 अगस्त, 1973, 31 दिसम्बर, 1973, 30 जून, 1974 और 31 दिसम्बर, 1974 तक बढ़ा दी थी।

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 30 जून, 1975 तक और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 30 जून, 1975 तक बढ़ाती है।

[सं० फा० 25/8/72-सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।